CLASS -11TH

भारत में आर्थिक सुधार

उदारीकरण, निजीकरण व वैश्विकरण

सन 1990 के आर्थिक संकट से भारतीय अर्थव्यस्था को निकलने तथा आर्थिक विकास को नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार से कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरम्भ किये जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है।

आर्थिक सुधार की आवश्यकता

भारत में आर्थिक सुधार 1991 में शुरू किया गया कयोंकि भरतीय अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हुए थे जिसके समाधान हेतु आर्थिक सुधारो की आवश्यकता का अनुभव किया गया। भारतीय अर्थयवस्था में उत्पन्न आर्थिक संकट निम्नवत थे –

1. देश में राजकोषीय घटा तीव्र गति से बढ़ रहा था वर्ष 1990 - 91 में यह 8 .4 % की ऊँचे स्तर पर था।

2. भुगतान संतुलन का संकट 10000 करोड़ तक बढ़ गया था।

3. 1990 - 91 भारत का विदेश ऋण सकल घरेलु उत्पाद का 23 % तक पहुंच गया था । विश्व बैंक एवं अंतरास्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को ऋण प्रदान करने मैं सहमत नहीं हो रहा था।

4 . सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक उपक्रमों का घाटा बढ़ता जा रहा था जो लाल फीताशाही एवं अकुशलता का परिणाम था।

5 . मुद्रा स्फीति तीव्र गति से बढ़ते हुए 18 % के उच्च स्तर पर पहुंच गयी थी ।

6 . 1990 - 91 मे विदेशी मुद्रा कोष बहुत ही कम था वे 10 दिन के आयात के मूल्य का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थे ।

नई आर्थिक नीति के तत्त्व

नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता भारतीय अर्थ व्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण करना है ।

उदारीकरण - उदारीकरण का अर्थ उद्योग एवं व्यापार पर सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, रक्षक कर, कोटा आदि को हटाना तथा इनकी प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि करना है । उदारीकरण में सभी व्यक्तिओं को आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है।

उदारीकरण की उद्देश्य - उदरीकरण की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. देश में रोजगार की अवसरों में वृद्धि करना ।

पदम सिंह फर्सवाण, प्रवक्ता अर्थशास्त्र

2. वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना ।

3. देश की आतंरिक तकनीक में सुधार करके उत्पादन की क्षमता का विकास करना ।

4. निजी उपक्रम एवं पूंजी पर लगे नियन्त्रों को हटाना ।

उदारीकरण की अंतर्गत अपनाये गए उपाय

1991 मैं उदारीकरण की प्रक्रिया की अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किये है ।

1. **औघोगिक क्षेत्र सम्बंधित सुधार** - सरकार ने औद्योगिक नीति 1991 में आरंम्भ की थी जिसमें मुख्य औधौगिक सुधार इस प्रकार है ।

(i) **उदारीकरण लाइसेंस नीति** - नई औद्योगिक नीति की अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्रों को 17 से घटाकर 3 तक लाया गया है सार्वजनिक क्षेत्र की लिए संरक्षित उद्योग रक्षा सयंत्र, आणुविक ऊर्जा उत्पादन, रेलवे परिवहन है 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के उद्योगों की लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है ये 6 उद्योग इस प्रकार है ।

(1) शराब

(2) सिगरेट

(3) औद्योगिक विस्फोटक

(4) रक्षा सयंत्र

(5) दवा एवं औषधियां

(6) हानिकारक रसायन

(ii) **लघु उद्योगों मैं निवेश सीमा बढ़ाना** - नई औद्योगिक नीति की अनुसार लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण करने हेतु निवेश सीमा 1 करोड़ कर दी गए है ।

(iii) **एकाधिकारिक कानून से छूट** - एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम (MRTP Act) मैं संसोधन किये गए बाद मैं सरकार ने MRTP अधिनियम को समाप्त करके प्रति स्पर्धा अधिनियम लागू किया गया।

(iv) **उत्पादन क्षमता का विस्तार** - उत्पादन क्षमता को पूर्व में लाइसेंसिंग के साथ जोड़ा गया था उदरीकरण से उत्पादन क्षमता पर लगे रोक से मुक्ति हो गयी है क्या उत्पादन करना है ? और कितन उत्पादन करना है ? उसका निर्णय अब उत्पादक स्वयं लेगा।

(v) **पूंजीगत वस्तुओं की आयत की स्वतंत्रता** - तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए उद्योग पतियों को पूंजीगत वस्तुओं की आयात की छूट दी गई है तकनीक की आयात की लिए अब सरकार से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

2. **वित्तीय क्षेत्र की सुधार**

वित्तीय क्षेत्र में तीन प्रकार की संस्थाए सम्मलित होती है।

1. बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाए
2. स्टॉक विनिमय बाजार
3. विदेशी विनिमय बाजार

भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक नियमन एवं नियंत्रण करता है उदारीकरण की पश्चात अब भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र की नियामक की स्थान पर सहायक की रूप में कार्य कर रहा है नियामक के रूप में रिज़र्व बैंक पहले व्यापारिक बैंकों की व्याज दर स्वयं निर्धारित करता था परन्तु अब सहायक के रूप में रिज़र्व बैंक बाजार शक्ति की स्वतंत्र क्रिया को सरल बनता है तथा व्याज दर का निर्धारण का निर्णय व्यापारिक बैंको पर छोड़ देता है।

3. **राजकोषीय सुधार** - राजकोषीय सुधारों का सम्बन्ध सरकारी आय एवं व्यय से होता है। कर सुधार भी राजकोषीय सुधार का प्रमुख घटक है। उदारीकरण से पूर्व देश में कर प्रणाली बहुत जटिल एवं अस्पष्ट थी कराधान के भार से लोग डर कर करों का भुगतान करने से बचने का प्रयास करते थे।

उदारीकरण की नीति लागू होने से कर नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए-

1. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया गया।
2. कर भुगतान की प्रक्रिया सरल बना दिया गया।
3. सरकार द्वारा अनियोजित व्यय को घटा दिया गया।

4. **विदेशी विनिमय सुधार** - 1991 में भुगतान संतुलन के संकट को तुरंत हल करने के लिए भारतीय रूपये का अवमूल्यन किया गया इससे हमारी वस्तुएं विदेशी बाजार मैं सस्ती हो गयी परिणाम स्वरुप विदेशी मुद्रा का देश मैं प्रवाह बढ़ा। अवमूल्यन के पश्चात भारतीय रुपए की विदेशी विनिमय बाजार मैं विनिमय दर की निर्धारण को बाजार शक्तिओं पर छोड़ दिया गया है वर्तमान मैं विनिमय दर का निर्धारण अंतराष्ट्रीय विनिमय बाजार में मांग था तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है।

5. **व्यापर नीति में सुधार** - 1991 से पहले भारत मात्रात्मक प्रतिबधो तथा आयातों पर उच्च सीमा शुल्क, आयात लाइसेंस तथा निर्यात कर द्वारा संरक्षण की नीति का पालन करता था जिसके परिणाम स्वरुप कुशलता एवं प्रतियोगिता की भावना कम हो गई । उदरीकरण की पश्चात व्यापार नीति ने भारतीय बाज़ारों को शेष विश्व की साथ जोड़ा है जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है ।

1. आयात कोटा समाप्त कर दिया गया ।
2. आयात लाइसेंसिंग नीति (पर्यावरण के लिए खतरनाक वस्तुओं को छोड़कर) को लगभग त्याग दिया है।

3. घरेलु बाजार में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए व्यापक रुप से आयात शुल्क में कमी कर दी गयी है ।

4. विदेशी बाजार में भारतीय वस्तुओं की प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क को वापस ले लिया है।

उदारीकरण के लाभ एवं हानियां

लाभ

1. उत्पादन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं ।
2. विदेशी निवेश की स्वतंत्रता।
3. उत्पादन इकाइयों की स्थापना में स्वतंत्रता ।
4. उधमियों को प्रोत्साहन ।
5. नई पूंजीगत वस्तुओं एवं तकनीक का प्रयोग ।

हानि

1. सामाजिक कल्याण की अनदेखी ।
2. एकाधिकार मे वृद्धि ।
3. आर्थिक विषमता में वृद्धि ।
4. कमजोर वर्ग का शोषण ।

निजीकरण

निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का स्वामी बन जाता है या प्रबंध करता है तथा उत्पादन की गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जाती है परन्तु सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप घटती जाती है निजीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कोई भी कदम उठाया जा सकता है।

1. ऐसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानो का प्रबंध एवं नियंत्रण जिसका सञ्चालन सरकारी विभगों की रूप में किया जा रफा था निजी उपकर्मियों को सौंप दिया जाये।

2. विराष्ट्रीकरण ।

3. सार्वजनिक क्षेत्र की विकास पर रोक लगा दिया जाये।

4. निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति देना जो की अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की लिए आरक्षित थे।

निजीकरण की उद्देश्य - वर्तमान में विश्व की विकाशील एवं विकसित दोनों प्रकार की देशों में निजीकरण का महत्त्व बढ़ता जा रहा है निजीकरण मैं निहित उद्देश्य निम्न है

1. देश की संसाधनों का उचित दोहन करना ।

2. उत्पादकता में वृद्धि करना ।

3. अर्थवयवस्था का आधुनिकीकरण, तकनीक का विकास एवं विस्तार ।

4. अर्थयवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाना ।

5. प्रबंधकीय योग्यता एवं कुशलता को बढ़ाना ।

6. बाह्यय ऋणों के भार को घटाना ।

7. नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना तथा आयात प्रतिस्थापन प्रक्रिया को बल देना।

निजीकरण हेतु उठाये गए उपाय

1. **आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र को इकाइयो में कमी** - भारत सरकार द्वारा 1991 की नई औद्योगिक नीति में आरक्षित सार्वजनिक इकाइयों की संख्या 17 से घटाकर 4 कर दियी गयी, अब सार्वजनिक क्षेत्र में रेल यातायात परमाणु ऊर्जा रक्षा सामग्री और परमाणु खनिजों का खनन ही शामिल है अब इनकी संख्या तीन रह गयी है।

2. **सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश** - भारत सरकार एवं कई राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों में अपने हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच रहे है ताकि नियंत्रण एवं प्रबंधन निजी हाथों मैं सौंपा जा सके।

3. **निजी क्षेत्र की योगदान में वृद्धि** - जुलाई 1991 में कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 63 % था में नई आर्थिक नीति मैं इसे कम करके 43 % कर दिया गया इस प्रकार भारत की मिश्रित अर्थ व्यवस्था मैं निजी क्षेत्र की पास कुल निवेश का 57 % योगदान होगा ।

निगमीकरण - निगमीकरण की अंतर्गत सार्वजनिक विभाग जैसे रेलवे बोर्ड आदि को कुछ स्वायत्तता देकर इन्हे लोकनिगम मैं बदलना चाहिए इससे रेलवे क्रियात्मक रुप से एक निजी संस्था में बदल जाएगी और एक लाभदायक नियम वन जायेगा ।

निजीकरण की लाभ व हनिया

लाभ

1. निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्रों की उद्यमों में लाभ दायकता एवं कुशलता उत्पन्न करता है।

2. वित्तीय घाटे को काम करता है ।

3. यह उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है ।

4. अफसरशाही पर नियंत्रण।

5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा ।

हानि

1. जनता का कल्याण एवं जीवन स्तर की अवहेलना ।
2. निजीकरण एकाधिकार को बढ़ावा देता है ।
3. अर्थव्यवस्था की असंतुलित वृद्धि होती है।
4. निजी क्षेत्र जोखिम वाले प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते है ।
5. निजी क्षेत्र दीर्घकालीन कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं चाहते है।

वैश्वीकरण

वैश्वीकरण निजीकरण तथा उदरीकरण की नीतिओं का उत्पाद है वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था मैं समाकलित करना है भारत में वैश्वीकरण 1991 की नीतिगत सुधारों द्वारा हुआ वैश्वीकरण का आशय प्रद्योगिकी, पूंजी, सूचना, वस्तु, सेवा आदि में विश्व के देशों के बीच आर्थिक निर्भरता को बढ़ाना है संक्षेप में देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना वैश्वीकरण है ।

वैश्वीकरण की चार प्रमुख अंग है

1. व्यापारिक बाधाओं को कम करना ताकि वस्तुओं का स्वतंत्र प्रवाह हो सके।
2. ऐसा वातावरण बनाना जिसे विभिन्न देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके।
3. ऐसी परिस्थिति सृजन करना टेक्नोलॉजी का निर्वाध प्रवाह हो ।
4. ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का बेरोकटोक प्रवाह हो सके

संक्षेप में विश्वीकरण के लिए वस्तुए, सेवाएं, पूंजी, टेक्नोलॉजी का आवागमन पर सभी तरह की बाधाएँ हटा ले जाती है।

भारत में विश्वीकरण को प्रेरित करने वाले घटक

तकनीक में परिवर्तन - भरत में विश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में तकनीकी परिवर्तन की प्रमुख भूमिका रही है तकनीकी परिवर्तन ने देश में उत्पादन लागत में कमी तथा उत्पादन मात्रा का विस्तार किया है।

प्रतियोगिता - अर्थव्यवस्था में खुले पन की कारण घरेलु उद्योगों ने स्वयं को विदेश तकनीक से जोड़कर विश्वीकरण से स्वयं को जोड़ा है।

उदारवादी नीतियां - भारत द्वारा अपनाई गए उदारवादी नीतिओं के कारण अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश प्रोत्साहित हुआ है जिससे विश्वीकरण का विकास हुआ है।

विकाशसील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव - विश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाने वाले विकाशशील अर्थवयवस्थाये जिसे कोरिया, थाईलैंड, ताइवान, होन्ग कोंग, सिंगापूर आदि में आर्थिक क्षेत्र में बहुत सफल

रहे विश्वीकरण की इस सफल अनुभव ने भी भारत जिसे अन्य देशों को भी अपनी अर्थव्यवस्था का विश्वीकरण करने की लिए प्रेरित किया।

उदरीकरण, निजीकरण व विश्वीकरण की नीतियों की प्रभाव

(अ) अनुकूल प्रभाव

1. विश्वीकरण में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी % 1990 में 0.6 % की स्तर से बढ़कर 2011 में 2 .5 % हो गया है।
2. विश्वीकरण की अपनाये जाने की बाद देश की विदेशी मुद्रा कोष में रिकॉर्ड बृद्धि दर्ज की गयी है।
3. भारत की निर्यातों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि दर्ज की गयी है।
4. भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बड़ी मात्रा मैं अंतर्प्रवाह प्राप्त करने में सफल रहा है।
5. विदेशी बाजार में भारतीय रूपया अधिक मजबूत हुआ है।
6. बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं की विस्तार ने भारत की औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन तकनीक को मजबूत आधार दिया है ।
7. अन्य अनुकूल प्रभाव
   - (i) विदेशी ऋणों की निर्भरता घाटी है।
   - (ii) विदेशी पूजी निवेश में बृद्धि हुई है ।
   - (iii) उद्योगों में तकनीकी उन्नयन करना संभव हुआ है।
   - (iv) देश की विकास दर में वृद्धि हुई है ।
   - (v) भारत को विश्व की सेवा व्यापार मैं प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है।

(ब) प्रतिकूल प्रभाव

1. **कृषि संकट** - LPG की नीतिओं ने कृषि की विकास दर को कम किया है
   - (i) कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक विनियोग में कमी आई है।
   - (ii) कृषि उत्पादों पर कृषि आयत शुल्कों की कटौती से भारतीय कृषि वस्तुओं का बाजार सीमित हुआ है।
   - (iii) किसानो ने अपने उत्पादन की संरचना को बदला है खाद्यान की स्थान पर निर्यात परक फसलों का उत्पादन बड़ा है जिससे खाद्यान की कमी हुई है।

2. **लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव** - LPG की नीतिओं का भारतीय लघु उधोगों पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है। लघु उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं की साथ कड़ी प्रतियोगिता करनी पढ़ रही है घरेलु लघु उद्योगों की उत्पादों की मांग घाटी है जिसका प्रतिकूल प्रभाव घरेलु उत्पादन एवं रोजगार पर पड़ा है।

3. **<u>लाभ का निर्यात</u>** - बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं ने भारत की श्रम बल एवं अन्य साधनो का उपयोग कर देश में अपने व्यवसाय का विस्तार किया है किन्तु इनके द्वार अर्जित लाभ का एक बड़ा भाग अपने देश को भेज दिया जाता है। भारतीय अर्थवयवस्था को वांछित लाभ नहीं मिलता है।

4. **<u>आय असमानताओं का विस्तार</u>** - बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं के कार्यविस्तार एवं निजीकरण ने कर्मचारिओं को ऊँचे वेतनमान दिए है किन्तु देश की बड़ी आबादी गांव में रहने के कारण जो इन बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं से अतरिक्त आय श्रोत प्राप्त करने में असफल रही है परिणाम स्वरुप देश में आय असमानता का विस्तार हुआ है।